Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, SEPT-OCT, 2021, VOL- 9/67
10.21922/srjis.v9i67.8238

मध्य बिहार में नक्सलवाद के विरोध में कृषकों का प्रतिरोध और रणवीर सेना की भूमिका

भानु कुमार
पीएचडी रीसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

Paper Received On: 21 OCT 2021
Peer Reviewed On: 31 OCT 2021
Published On: 1 NOV 2021

Abstract

मध्य बिहार 90 के दशक में कृषक संघर्ष और नक्सलवाद का केंद्र बनकर उभरा था। इस संघर्ष को राज्य की उदासीनता ने जातीय संघर्ष का रूप दे दिया। मध्य बिहार में बदलते रजनीतिक,सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को इस लेख के मध्याम संसें समझा जा सकता है। साथ हीं राज्य, जाति और विचारधारा के आपसी टकराव पर आधारित हिंसा को भी लेख के द्वारा समझने का प्रयास किया गया है।

***Key Words**: नक्सलवाद, रणवीर सेना, कृषक आंदोलन, खेतिहर आंदोलन, भूमहिन, सामाजिक परिवर्तन,सामंती कृषक प्रणाली, जातीय नरसंहार।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

अध्ययन-प्रणाली :

इस लेख के अध्ययन में सैद्धांतिक,एतिहासिक,तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन-प्रणाली का उपयोग किया जाएगा | इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग मध्य बिहार के सामाजिक,राजनितिक एवं अन्य सम्बंधित कारकों के आयामों को समझने में किया गया है, इस लेख को लिखते हुए एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है जिसके अंतर्गत मध्य बिहार के सम्बंधित जिला और गांव को केंद्र बनाकर अध्ययन किया है| अध्ययन के संदर्भ में उद्देश्य स्पष्ट है कि मध्य बिहार के अंदर जमीन को एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से अधिकार से जुड़ा हुआ है तथा यह किस प्रकार राज्य,समाज एवं विचार को प्राभावित कर रहा है | जाति आधारित सेना,नक्सलवाद का जातीय स्वरुप को समझने के लिए भी हमें तथ्यात्मक एवं विशलेषनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है | रणवीर सेना एवं नक्सलवाद के संगठन एवं इसके समर्थन के आधार को समझने के लिए उपलब्ध लेखों का प्रयोग किया जाएगा |

पृष्टभूमि :

बिहार में भूमि के मसले पर किसान एवं खेतिहर मजदूरों के बीच संघर्ष और विमर्श व्यापक रूप विवादित रहा है | अंग्रेजों के आने के बाद जमींदारी व्यवस्था एवं इसकी समाप्ति तक बिहार में भूमि के अधिकार, शक्ति का केंद्र

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

व्यापक रूप संकुचित हो गया था | इस व्यवस्था की समाप्ति ने भूमि के वितरण को संभवकिया,जो हमें दो प्रकार की राजनीति की ओर इशारा करता है , एक ओर भूमि का हस्तांतरण जो शक्ति की राजनीति के अखाड़े को तैयार कर रहा था वहीँ दूसरी ओर राजनितिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर रहा था | जिसका सीधा संबध शक्ति का सामंती प्रणाली (The Feudal Mode of Power) से था जहाँ प्रभुत्वकारी प्रक्रिया अधीनस्थता की अवधारणाओं पर चल रही थी | जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति ने भूमि का वितरण तो किया गया, किन्तु शक्ति का विभाजन करने में असफल रहा , जिसके कारण विगत वर्षों में व्यापक संघर्ष देखने को मिला |भारत में कृषक आंदोलन को सामान्यतः स्वतंत्रता से पूर्व (Pre-Independence) और स्वतंत्रता के बाद (Post-Independence) के कालों में विभाजित करके देखा जा सकता है| जैसा कि ए आर देसाई का मानना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के आंदोलन के लिए "कृषक आंदोलन" एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, दूसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आंदोलनों के लिए "खेतिहर आंदोलन" की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है| स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के "कृषक आंदोलन" जहां सिर्फ खेतिहर मजदूरों, बटाईदारों, निर्धन व सामंत अधीन कृषकों तक सीमित था वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कृषक आंदोलन में न केवल कृषक बल्कि अन्य लोगों से तालुकात रखता है | इस लेख में कृषक का सरोकार राजनितिक है जिसके अंतर्गत नक्सलवाद के भूमि पर जबरन अतिक्रमण के प्रतिरोध में रणवीर सेना की राजनीतिक कार्यवाही को समझने से है | इस लेख में कृषक सामाजिक व्यवस्था के आंतरिक संरचना में बदलाव स्वरुप हो रहे घटनाओं को समझने का भी प्रयास किया जाएगा, साथ हीं साथ नक्सलवाद द्वारा भूमि वितरण को लेकर प्रस्तुत किये जा रहे नए आयामों को भी विश्लेषित किया गया है |

कृषक प्रतिरोध तथा राजनीति:

यद्यपि, भारत में कृषक की अवधारणा एक राजनितिक अवधारणा है, जो ऐसे उपागम का मार्ग प्रशस्त करता है जहाँ हमें आधुनिक राजनीति के सन्दर्भ में कृषकों आन्दोलन के ताकतों और कमजोरियों के साथ सम्पूर्ण कृषकों या कृषकों के हिस्सों के संगठनिकरण के अवसरों के दोनों के ऐतहासिक सन्दर्भों को साथ हीं, दुसरे वर्गों एवं समूहों द्वारा समझने का व्यापक विस्वसनीयता का सुराग देता है, यह दृष्टिकोण कृषकों के भीतर विभेदीकरण के संभतः अपरिवर्तनीय प्रक्रिया की ओर झुकाव को दर्शाता है |

मध्य बिहार के पटना,गया,अरवल,जहानाबाद,...मुख्य रूप से धान के खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है | धान के खेती के लिए व्यापक स्तर पर मजदूरों की आव्श्याकता को पूरा करने के लिए पूर्व-ओपनेवाषिक काल से लेकर 1890तक दलित एवं अन्य पिछड़े जाति के गांवों को कृषि कार्यों के लिए बसाया गया| आज़ादी के पश्चात् जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति के बाद भूमि वितरण का सबसे अधिक लाभ अन्य पिछड़े जातियों विशेषकर कुर्मी,कोएरी एवं यादवों को मिला तथा आंशिक लाभ दलितों को प्राप्त हुआ, किन्तु यही वर्ग जमींदारी उन्मूलन के बाद पूर्व ज़मींदारों (जो मध्य वर्गीय किसान के रूप में परिवर्तित हो चूका था) के लिए भस्मासुर बन गए |

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ज़मीनदारी व्यवस्था का उन्मूलन की आंशिक विफलता एवं बिहार में भूदान आन्दोलन के ज़मीनों का उचित वितरण न हो पाने के कारण नक्सलवाद के मुद्दे को व्यापक समर्थन समाज के निचले तबके एवं भूमिहीन मजदूरों से मिला | नक्सलवाद आन्दोलन के जन्म ने बिहार के भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हिंसक विरोध के लिए प्रेरित किया तथा एक हिंसक एवं संगठित वैचारिक संघर्ष की राजनीति की शुरुआत की, जिसके प्रतिरोध में कृषकों के सभी जाति (राजपूत,भूमिहार, कुर्मी,कोएरी,यादव) का प्रतिरोध देखने को बाद के काल खंड में मिलता है |
स्वतंत्र बिहार में इसका प्रथम उदहारण पटना के आसपास में देखेन को मिलता है|1970 के दशक आते आते नक्सलवाद के आंदोलनों के अंतर्गत पटना के पुनपुन एवं मसौढ़ी प्रखंडों में कुर्मी जाति के ज़मीनों पर नक्सलवादीयों ने कब्ज़ा कर उनका वितरण शुरू कर दिया | मध्य वर्गीय किसानों को अपने ज़मीन की सुरक्षा के लिए अपने हीं भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो नक्सलवाद के वैचारिक झंडे के साथ संघर्ष कर रहा था उसका प्रतिरोध करना पड़ा |कुर्मी जाति ने अपने ज़मीनों को नक्सलवाद के प्रभाव से बचने के ले 'भूमि सेना' का निर्माण किया जो नक्सालवाद के संघर्ष एवं हिंसा का उत्तर उन्हीं के भाषा में देने का प्रयास किया | भूमि पर किसका अधिकार हो, इसको लेकर यह संघर्ष निरंतर चलना शुरू हो गया | 1990 के पश्चात मध्य बिहार में नक्सलवाद ने काल्पनिक जमींदार के विरुद्ध अपना हिंसक संघर्ष शुरू किया | नक्सलवाद का आधार एवं विचार इस काल खंड में पूर्व से व्यापक परवर्तित हो चूका था | नक्सलवाद अब भूमिहीन खेतिहर मजदूर विशेषकर दलितों एवं पिछड़ों को मध्य-वर्गीय किसानों के विरुद्ध संगठित कर रहा था |मजदूरी बढ़ाने के मांग तथा 'सामाजिक इज्ज़त एवं प्रतिष्ठा' इस हिंसक विरोध की लडाई का मुख्य आधार शुरुआत में रहा जो धीरे धीरे जाति आधारित संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया | 1994 में भोजपुर जिले के बेलाऊर गाँव में नक्सलवादीयों ने मजदूरी बढ़ाने के मांग पर धान की खेती का चालीस दिनों तक नाकेबंदी कर दी जिस कारण से इसके बाद लगभग 40 हज़ार एकड़ ज़मीन परती रह गया ,जिस कारण से किसानों को प्रतिउत्तर देने अक्टूबर 1994 में रणवीर सेना समिति का निर्माण किसानों के संगठन के रूप में किया गया तथा यह स्पष्ट किया गया की यह ज़मींदारों के हितों की रक्षा के लिए नहीं बना है | बाद में इस संगठन का नाम बदल कर रणवीर संग्राम समिति कर दिया गया| मध्य बिहार में पूर्व जमींदार 1970 के दशक आते-आते लगभग नगण्यता की स्थिति में पहुँच चुके थे, साथ हीं साथ उच्च जाति के मध्य एवं निचली स्तर के कृषकों के पास भी औसत ज़मीन 20 एकड़ से लेकर 6-7 एकड़ तक शेष रह गये थे, जो 1990 के दशक आते आते 5 एकड़ तक पहुँच गया |भूमि पर अधिकार को लेकर संघर्ष में रणवीर सेना एवं नक्सलवाद के मध्य लगभग एक दशक तक का हिंसक टकराव चलता रहा| जो मुख्य रूप से ग्रामीण कुलीनतंत्र एवं प्रत्यक्ष उतपादक वर्ग के संघर्ष को दर्शाता है | संघर्ष के रूप में परिवर्तन के कारण यह जातिगत हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया जिस कारण से कई नरसंहार देखने को मिलता है |रणवीर सेना के संघर्ष में दोनों पक्षों द्वारा व्यापक रूप में नरसंहार देखने को मिला | इस हिंसक घटनाओं का उदाहारण देखे तो 1997 जहाँ रणवीर सेना द्वारा 60 से अधिक नक्सली (दलित जाति के सदस्य) को मारा गया तो 1999 में सेनारी हत्याकांड में रणवीर सेना के लगभग 50 से अधिक लोग(भूमिहार जाति) मारे गये | MCC बिहार में रणवीर सेना के जन्म का मुख्य

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कारण CPI(ML) के संशोधनवादी निति को मानता, जिसके अंतर्गत 1989 से इस दल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना शुरू किया तथा किसानों के विरुद्ध हिंसक गुरिल्ला दल को निरस्त कर दिया, जिसकारण से नक्सलवादी संगठन को खुले संघर्ष के लिए आना पड़ा ,परिणाम स्वरूप प्रतिरोधी रणवीर सेना का जन्म हुआ|
उपरोक्त चर्चा से इस बिंदु पर स्पष्टता आवयशक है कि क्या नक्सलवाद तथा इसके खिलाफ जन्मा रणवीर सेना के आंदोलन क्या सामाजिक आँदोलन है या जन आन्दोलन है साथ हीं, आज के वर्तमान सामाजिक आन्दोलन के विमर्श में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है | हालाँकि इस प्रश्न के प्रसंग में सीधे तौर पर किसी निषकर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है लेकिन परिभाषित तौर पर सामाजिक आन्दोलन का अर्थ बहुत धुंधला है ,यह किसी भी विशेष मुद्दे पर लोगों की गोलबंदी के बारे में बताता है जिसका स्वस्थ्य उदहारण आजके सन्दर्भ में नक्सलवाद है | यह विशेष मुद्दे के आसपास हीं घूमता हुआ प्रतीत होता है | जबकि नक्सलवाद के खिलाफ जन्मा रणवीर सेना का आँदोलन का दायरा मौलिक रूप से अधोस्तरीय रहा है | जाति आधारित नरसंहार, मध्य बिहार में कृषकों के प्रतिरोध स्वरुप जन्मा सामाजिक आन्दोलन के विमर्श को एक नए तरीके से देखने के लिए भी प्रेरित करता है, जहाँ इस आन्दोलन में हिंसा को हीं समाज स्वीकृति प्रदान करता है | नक्सलवाद अपने वैचारिक आधार पर हिंसा का सहारा लेता है तो रणवीर सेना हिंसा के वैचारिक आधार को सर्व-प्रथम अपने जाति विशेष के इतिहास से लेता है तत्पश्चात उसे कृषक अधिकारों से जोड़ देता है |

विषय को समझने के लिए निम्नलिखित साहित्य का विश्लेषण किया गया है :

जैसा की पार्था चटर्जी अपने लेख The Colonial State and Peasant Resistance in Bengal 1920-1947 (Past and Present, Feb.1986) में स्पष्ट करते हैं कि कृषकों के राजनितिक प्रक्रिया में विशिष्ट व्यक्तिपरकता होती है जो परिवर्तन को ले आती है | कृषकों के व्यक्तिपरकता को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए |कृषकों की राजनीति को आदिकालिक पूर्व-राजनितिक अतार्किक मान कर इन्हें स्वाभाविक रूप में तथा इनके कार्यकलापों को नज़रंदाज़ नहीं करना चाहिए अपितु इनकी क्रियाओं को जो स्वयं की चेतना से अप्रमाणित है जिसका निर्माण कई सदियों के स्वयं के ऐसे राजनितिक इतिहास से हुआ जो शक्ति और नैतिकता के विशिष्ट धारणाओं से निर्मित है जो वर्ग संघर्ष की पुर्णतः नवीन सन्दर्भों में तालमेल एवं कार्यवाही करने का प्रयास कर रहा है | यह एक ऐसी उपागम के रूप में सामने आता है जहाँ आधुनिक राजनीति के सन्दर्भ में कृषकों के ताकतों और कमजोरियों को सांगठनिककृत कर देता है

अश्वनी कुमार अपनी पुस्तक कम्युनिटीवारियर: स्टेट,पिजन्ट्स एंड कास्ट आर्मी इन बिहार (एंथम पब्लिकेशन:2008)में रणवीर सेना के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया है | अपने अध्ययन में उन्होंने रणवीर सेना के सामाजिक, राजनीतिक, सांगठनिक एवं नरसंहार में भूमिका की व्यापक चर्चा की है| अश्वनी कुमार के अनुसार रणवीर सेना एक जाति विशेष अर्थात भूमिहार जाति के सेना के रूप में समाज के निचले तबके एवं भूमिहीन किसानों के विरुद्ध संघर्षरत निजी सेना थी | अश्विनी कुमार के अनुसार बिहार सरकार द्वारा रणवीर सेना पर प्रतिबंध के बावजूद यह निजी सेना दलितों एवं अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के नरसंहार में व्यापक रुप से

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संलग्न रहा है| भोजपुर जिला में जन्मे रणवीर सेना शुरुआत में एक किसान संघर्ष के रूप में स्वंय को दिखाने का प्रयास किया गया| जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, गया,बक्सर और पटना के आसपास के इलाकों में इस निजी सेना को व्यापक रूप में समाज के उच्च जाति एवं पिछड़े जाति के जमींदारों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ | बिहार में बढ़ते हुए नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने के लिए इस सेना का गठन किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया कि रणवीर सेना को व्यापक स्तर पर राजनीतिक एवं आधिकारिक तंत्र का समर्थन प्राप्त है | अश्विनी कुमार ने अपनी पुस्तक में रणवीर सेना के निर्माण एवं इसके वैचारिक आधार जो विशेषकर जाति पर निर्भरता का विश्लेषण किया, साथ हीं रणवीर सेना द्वारा हिंसक घटनाओं को नक्सलवाद एवं जमीन पर स्वामित्व संघर्ष के रूप में चित्रण किया | रणवीर सेना हिंदुत्व एवं राष्ट्र के विचार के संदर्भ में स्वयं को परिभाषित करने का प्रयास किया जिसके अनुसार सेना राष्ट्र की संकल्पना को आधार मानकर जातीय वरीयता में अपने स्थान एवं विचार को सबसे ऊपर स्थापित किया जा सके | जातीय आधार पर संगठित रणवीर सेना नक्सलवाद को वैचारिकदुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया तथा व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस के लिए प्रेरित किया | इस पुस्तक में रणवीर सेना के संगठन का भी व्यापक विश्लेषण किया गया है | लेखक के अनुसार मध्यवर्गीय किसानों के मध्य भविष्य चिंता की बात,संगठन के अंदर साधारण भाषाओं में व्यवहार,नेतृत्व में विश्वास तथा संगठन का केंद्रीय तथा सीक्रेसी एवं संसाधनों का उचित प्रबंध होने के कारण रणवीर सेना अपने पूर्ववर्ती संगठनों व्यापक स्तर भिन्न पर था | रणवीर सेना को राज्य के विभिन्न अंगों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था | भारतीय जनता पार्टी एवम समता पार्टी के नेताओं से नजदीकियां एवं अधिकारिक तंत्र में जातिगत समर्थन होने के कारण इसके राज्य से काफी कम चुनौती प्राप्त हुआ | तरफ राज्य नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में शामिल था तथा अप्रत्यक्ष रुप से रणवीर सेना की भूमिका पर अपनी तटस्थता बरकरार रखी वहीँ दूसरी तरफ नरसंहारों में दोनों पक्षों की भूमिका को लेकर राज्य न्याय पूर्ण व्यवहार करने में असफल रहा | चुनावों के समय राजनीतिक दलों द्वारा रणवीर सेना का व्यापक स्तर पर प्रयोग देखने को मिलाता है, जिस कारण रणवीर सेना व्यापक रुप से मध्य बिहार की राजनीति का अभिन्न अंग बन कर कार्य कर रहा था | लेखक ने अपने पुस्तक के पुरे विवरण में हिंसा एवं अन्य पक्षों पर एकांगी दृष्टि प्रस्तुत किया है | अर्थात शोध के दृष्टि से रिक्त स्थान को भरने की आव्श्याकता शेष रह जाती है |

हिमांशु रॉय फ्रंटियर के अपने लेख Contextualizing Ranveer Sena (2012) में लिखते हैं कि मध्य बिहार में सीपीआई एम एल लिबरेशन के गुरिल्ला संगठनके विरुद्ध जन्मा था | खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीन किसानों द्वारा इज्ज़त एवं अपने मजदूरी की मांग को हिंसक रूप में मनवाने के लिए किए जा रहे हैं प्रतिरोध तथा सीपीआई एम एल लिबरेशन द्वारा किसानों के खेतों की नाकाबंदी (इसका उदाहरण बेलापुर गांव में देखने को मिलता है) के कारण इस संगठन की रचना की गयी | किसानों के विरुद्ध बढ़ते नक्सलवाद एवं भूमि पर कब्जा तथा कृषि व्यवस्था की चुनोतियों से सामना करने के लिए मध्यवर्गीय किसानों के द्वारा शुरुआत की गयी, जिसे समाज के विभिन्न जातियों का समर्थन प्राप्त था| दिल्ली आधारित मीडिया घरानों एवं बुद्धिजीवियों ने इस संगठन को उच्च जाति के जमींदारों के निजी सेना के रूप में इसे परिभाषित प्रयास किया | किंतु वास्तविक स्तर पर यह संगठन

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उन किसानों का था जिनकी औसत भूमि 5 एकड़ के आसपास शेष रह गई थी| हिमांशु राय रणबीर सेना की अवधारणात्मक के बहसों की शिनाख्त करते है, मध्य बिहार में उच्च जाति के किसानों की स्थिति जमीनदारी व्यवस्था की समाप्ति के बाद OBC एवं दलित जो इस व्यवस्था से लाभांवित हुए थे बदतर स्थिति हो गई थी | बिहार में नरसंहार एवं जातीय हिंसा के विषय परलेखक रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया के संदर्भ में को बताते हुए कहते हैं की हमेशा से रणवीर सेना द्वारा दलित एवं अन्य लोगों पर किए जा रहे हिंसा का एकपक्षीय स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है ,वही सी पी आई एम एल लिबरेशन द्वारा किए गए हिंसा एवं जाति केंद्रीय नरसंहार को व्यापक स्तर पर नजरअंदाज किया जाता रहा है| एक पक्ष को जमींदारों की हिंसा के रुप में दर्शाया जाता है ,तो दूसरे को क्रांतिकारी घोषित किया जाता है| रणवीर सेना को जमीनदारी प्रथा से लाभांवित हुए समाज के विभिन्न जाति विशेषकर कुर्मी, कोइरी, यादव एवं दलितों के कुछ विशेष जाति तथा उच्च जाति के ब्राह्मण एवं राजपूत का समर्थन इस संगठन को हमेशा से रहा जिस कारण से समाज में इसके विरुद्ध कोई भी आन्दोलन या विरोध का सुर नहीं देखने को मिला | वैचारिक स्तर पर देखा जाए तो यह किसानों के दो वर्गों का संघर्ष ज्ञात होता है , एक तरफ मध्यवर्गीय किसानों का प्रतिनिधित्व रणवीर सेना कर रहा था तो दूसरी तरफ खेतीहर मजदूर एवं भूमिहीन किसानों का प्रतिनिधित्व नक्सलवाद कर रहा था | लेखक रणवीर सेना को बिहार में कृषि से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के मांग को लेकर राज्य एवं नक्सलवाद के विरोध में एक ऐसा संगठन मानता है जो समय के साथ किसानों के स्थिति से चिंतित था एवं इनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था | रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया का बिहार एवं इससे बाहर स्वीकार्यता यह दर्शाता है की किसानों को अपने हितों की रक्षा के लिए हिंसक संघर्ष भी समाज को स्वीकार्य है|

विकास कुमार झा ने अपने पुस्तक बिहार राजनीति का अपराधीकरण (राजकमल प्रकाशन:2005)में मानते हैं की जमींदारी प्रथा के उचित वितरण न होने के कारण भूमि के लिए संघर्ष देखने को मिलता है | मध्य बिहार में राज्य की विफलता एवं अपने को इस प्रक्रिया से बाहर करना हिंसा का बड़ा कारन बना | ज़मीन वितरण पर लेखक अजित सरकार के भाषण का उदाहरण देते हुए कहते हैं की ज़मीन वितरण में अनियमितता ने किसानों एवं मजदूरों को आपसी संघर्ष के लिए विवश कर दिया | इस बात की पुष्टि रणवीर सेना एवं नक्सलवाद के मध्य संघर्ष के रूप में देखने को मिलता है | विकास कुमार अपने इस पुस्तक जातीय संघर्ष को राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के रूप में भी समझने का प्रयास किया गया है | लेखक राज्य,जाति,वर्ग एवं अन्य के मध्य बदलते संघर्ष एवं राजनीतिक शक्ति का हस्तातंरण नए वर्गों में होने को भी इस हिंसा का कारन मानते है | अर्थात शक्ति के प्रवाह ने भी नए विवादों का जन्म दिया जिसका उदाहरण रणवीर सेना एवं नक्सलवाद के मध्य संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है |

बेला भाटियाअपने लेखThe Naxalite Movement in Central Bihar (EPW:2005) मैं यह विमर्श दर्शाने का प्रयास करती हैं की मध्य बिहार में नक्सलवाद ने दलितों एवं शोषितों को व्यापक रुप में सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | उनके अनुसार बिहार के ग्रामीण परिवेश में नक्सलवाद के उदय ने भूमि आधारित

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ग्रामीण शक्ति के केंद्र को व्यापक रूप में परिवर्तित किया| नक्सलवाद की राजनीति विकास केंद्रित ना होने के कारण करीब दलित शोषित एवं पिछड़ों के जीवन में व्यापक परिवर्तन तो संभव ना हो सका किन्तु सत्ता के साथ संवाद करने में सक्षम बना दिया | नक्सलवाद एवं विकास दो पर्यायवाची शब्द ना होने के कारण तथा नक्सलवादी नेताओं का राज्य के विकास में विश्वास ना होना रहा है धीरे-धीरे यह आन्दोलन लगभग मृत होता जा रहा है | विभिन्न संगठन से लंबे संघर्ष ने बिहार में नक्सलवाद को जनमानस से धीरे धीरे दूर करना शुरु कर दिया| नक्सलवाद में आपसी गुटबंदी एवं सांगठनिक कमजोरी ने इस आंदोलन को लगभग समाप्त कर दिया है | अर्थात एक तरफ इसने शोषित और गरीबोँ को मजबूत तो किया किन्तु विकास से दूर रखने के कारण इन्हें अपने स्थिति में पुनः पहुंचा दिया | बेला भाटिया बिहार में नक्सलवाद को दो भागों में बांट कर देखती हैं प्रथम भाग 1970 के दशक से पूर्व का है जब यह बिहार के 2-3 जिलों तक सीमित था, दूसरा भाग आपातकाल के दौरान राज्य द्वारा व्यापक अतिक्रमण के कारण देखा गया जब इसके संगठन के स्वरुप में व्यापक विस्तार देखने को मिला | संगठन के इस विस्तार एवं स्वीकार्यता ने इन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया |

प्रकाश लुइस अपने पुस्तक People Power: The Naxalite Movement in Central Bihar(Wordsmith:2002) में मध्य बिहार के नक्सलवादियों एवं कृषक मजदूर संगठनों के सामाजिक आर्थिक एवं संगठन चर्चा को अपना विमर्श का विषय बनाया है | इस पुस्तक में नक्सलवाद के मध्य बिहार में जन्म लेने के कारण, समाज में विभिन्न वर्गों से मिलने वाला सहयोग, इसकी प्रति राज्य का दृष्टिकोण तथा इसके विकास के फलस्वरूप जमींदारों से संघर्ष की घटनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है | निष्कर्ष : लेखक इस पुस्तक में मध्य बिहार के सामाजिक संरचनाओं में दलितों एवं शोषितों के पिछड़ेपन तथा उच्च वर्ग से मिलने वाले प्रताड़ित के कारण संघर्ष को एक नया आयाम माना है ,जो मध्य बिहार में शक्ति का समाज के निचले जिससे तक पहुंचाने एवं कुलीनतंत्र को चुनौती प्रदान करने में समर्थता को दर्शाता है | इस पुस्तक में में नक्सलवाद को जन-शक्ति के रूप में दर्शाया गया है| उनके अनुसार नए बिहार में शोषित एवं समाज से बहिष्कृत लोगों को नक्सलवाद की ओर आशा के रूप में देखने के लिए विवश होना पड़ा | नक्सलवाद के विचारों से इनका सीधा संवाद होने के कारण इन्हें शक्ति का एहसास सर्वप्रथम हुआ जो भविष्य में मध्य बिहार में जनशक्ति एवं इसके विरोध की संघर्ष की कहानी बन कर सामने आई |लेखक ने राज्य की भूमिका को जन-शक्ति के राजनीति में सहायक होने की बात को भी संदर्भिक रूप में परिभाषित करता है |

रणवीर सेना एवं नक्सलवाद के मध्य बिहार में जातीय संघर्ष की घटना कोई नई बात नहीं है ।वर्ष 2009 में डी बंद्योपध्याय द्वारा किए गए भूमि सुधार आयोग की रिपोर्टमें जातीय हिंसा का एतहासिक चर्चा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1965 से लेकर वर्ष 1985 तक के बीच जो नरसंहार हुए, उनका मूल कारण भूमि सुधार की समस्या थी,एवं उसके पश्चात की भी घटनाओं में भूमि हीं केंद्र में रहा किन्तु अब कारणों में व्यापक परिवर्तन आ गया। अपनी रिपोर्ट के प्रारंभ में ही डी. बंद्योपध्याय ने स्पष्ट किया कि भूमि सुधार सही प्रकार न होने के कारन, बिहार आज भी बमों के ढेर पर टिका है, जिसमें कभी भी आग लग सकती है।निश्चित ही यह बंद्योपध्याय का

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

साहस था कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सारे नरसंहारों के सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन किया। मसलन यह कि किस नरसंहार में किस जाति के लोग आक्रमणकारी थे और किस जाति के लोगों का रक्त बहा। इनकी रिपोर्ट को देखें तो अधिसंख्य मामले आक्रमणकारी जाति की सूची में कुर्मी जाति का उल्लेख मिलता है जो 1990 के दशक में बदल कर भूमिहार जाति पर केन्द्रित हो गया । कुर्मी जाति के व्यापक उल्लेख के कारण हीं संभवतः नीतीश सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न मध्यवर्गीय कृषक जातियों, छोटे सामंती तबके के मध्य सम्बन्ध 1970 से नक्सलवाद के हस्तक्षेप के बाद बिगड़ना शुरू हुआ जो लालू यादव के सत्ता आगमन के बाद व्यापक एवं संगठित हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया ।

PUDR की रिपोर्ट पीयूडीआर Agrarian Crisis in Bihar and the Ranbir Sena (PUDR:1997)ने अपनी रिपोर्ट में बिहार के विभिन्न जिलों में रणवीर सेना द्वारा किए गए हिंसक वारदातों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया |इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हिंसा का कारण मुख्यतया कृषि से संबंधित है जो कि उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों पर अधिपत्य को दर्शाता है एवं रणबीर सेना द्वारा हिंसा मुख्यतया जातीय हिंसा है | पीयूडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया की मध्य बिहार में उद्योगों का अभाव होने के कारण मजदूर मुख्य रूप से कृषि कार्यों पर ही निर्भर है तथा सामाजिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव नहीं देखने को मिला है| पीयूडीआर ने रणवीर सेना द्वारा संघर्ष का मुख्य कारण दलितों-पिछड़ों एवं शोषितों द्वारा अपने हिस्से के जमीनों पर अधिकारों को लेकर उत्पन्न हुआ मानता है| जमीनदारी प्रथा खत्म होने के बाद भी वितरित जमीन उचित लोगों तक नहीं पहुंच पाई है इस रिपोर्ट के अनुसार यह संघर्ष समाज के निचले हिस्से का संघर्ष है जो कृषि कार्यों में सदा से मुख्य उत्पादकता रहा है एवं अपने हक़ की मांग कर रहा था पीयूडीआर के अनुसार रणवीर सेना मध्यवर्गीय किसानों का नहीं वरन जमींदारों का संगठन है जो अपने स्वामित्व एवं पुरानी स्थिति को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है | भाजपा के विभिन्न सदस्यों का समर्थन इस संगठन को प्राप्त है जिस कारन से यही व्यापक रूप संगठित हो पाया | अर्थात उच्च जातियों के सामाजिक,राजनितिक स्वीकृत ने इस सेना को अपने पूर्वर्ती से भिन्न एवं ज्यादा प्रभावकारी बना दिया |

बिहार में हुए नक्सलवाद एवं कृषक संघर्षों ने जो जातीय नरसंहार का रूप लिय था उसका परिणाम आज भी बिहार की सामाजिक संरचना पर स्पष्ट दिखाई देता है। राज्य के उदासीनता ने जो इस क्षेत्र में लोगों के बीच निराशा का भाव उत्पन्न किया था उसका समाधान समय के साथ तो हो गया किंतु हिंसा और टकराव का मूल कारण आज भी निरुत्तर है।

References

Kumar, Ashwani. 2008. Community Warriors: State, Peasants and Caste Armies in Bihar. New Delhi: Anthem Press.

Guha.Ranajit.1993.(eds.). SuubalternStudies.Vol1.NewDelhi;OUP

Mukharjee and Yadav. Kalyan.R.S.1980.Bhojpur:Naxalism in the Plains of Bihar:NewDelhi.Radha Krishna

Chaudhary.A.K.2010.Contemporary Politics and Changing Economy of Bihar.Patna.Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies.

Roy.Himanshu.21Feb.1998. Of Ranveer Sena and CPI(ML).Kolkata.Frontier.

Roy.Himanshu.Nov.2014.An Alternative Peseant Movement. Paper Presented at NMML.

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Alkire, Sabina. 2003. A Conceptual Framework for Human Security. Working Paper 2, Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE). London, Queen Elizabeth House: University of Oxford.

Nimbram, A. S. 1992. Poverty, Land and Violence: An Analytical Study of Naxalism in Bihar. Patna: Laymans Publications.

Pathak, B. 1993. Rural Violence in Bihar. New Delhi: Concept Publishing House.

People's Union for Democratic Rights. 1997. Agrarian Conflict in Bihar and the Ranbir Sena. New Delhi: October.

Prasad, P.H. 1994. Poor Peasant Movement in Central Bihar. In K. K. Sharma, P. P. Singh, Ranjan Kumar, eds., Peasant Struggles in Bihar 1831 - 1992. Patna: Janaki Prakashan.

Prasad, B. N. 2006. Threat to Hegemony: 'Senas' in the Agrarian Social Formation. Paper Presented in the 32nd All India Sociological Conference, Chennai: University of Madras and Loyola College.

P.U.C.L. 1992. Report on Massacre in Men and Barsiwan. Patna: P.U.C.L. Bihar State Unit.

Rothschild, Emma. 1995. What is Security?. Daedalus 124(3): 53-98.

Sharma, A.N.(eds.) 1997. Bihar: Stagnation or Growth. Delhi: Spectrum Publishing House.

Singh, Prakash. 1995. The Naxalite Movement in India. New Delhi: Rupa

Thomas, Caroline. 2000. Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality. London and Sterling, VA: Pluto Press.

United Nations Development Programme (UNDP). 1994. Human Development Report 1994. New York: Oxford University Press.

Bajpai, Kanti. 2000. Human Security: Concept and Measurement. Kroc Institute Occasional Paper 19, Notre Dame, Indiana: Joan S. Kroc Institute for International Peace Studies.

Banerjee, S. 1984. India's Simmering Revolution: The Naxalite Uprising. New Delhi: Select Book Service Syndicate.

Bhatia, B. 2005. The Naxalite Movement in Central Bihar.Economic and Political Weekly, April 9, Mumbai.

Bhattacharya, Prabodh. 1986. Report from the Flaming Fields of Bihar (CPI (ML) Document). Calcutta.

Dhawan, H. 1992. Bitter Harvest (PUDR Report). Delhi: PUDR.

Desai.A.R.1986. (eds.). Agrarian Struggles in India after Independence. Delhi: Oxford University Press

Bandyopadhyay.D.2009.Land Reforms Commission Report. Bihar Government

Sinha and Pushpendra.B.K.2000(eds). Land Reform in India,(Vol. V).New Delhi:Sage Publication.

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies